



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

*5/11/90*

भाग-II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रापिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1989/आषाढ़ 28, 1911

No. 518] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1989/SAVANA 28, 1911

इस भाग में अधिन वृष्टि संस्कृत दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
इच्छा द्वारा उपलब्ध हो।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(आधिकारीय विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1989

का आ. 652 (प्र).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी  
विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा  
45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय  
रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के  
पश्चात बैंक आौफ अंजावुर लिमिटेड की बाबत 19 अगस्त, 1989  
को कारबाह की समाप्ति से तारीख 19 दिसम्बर,  
1989 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि  
के लिए अधिस्थान आदेश करती है और अधिस्थान की  
कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध

सभी कारबाहियों और कार्यबाहियों के प्रारम्भ करने या  
चालू रखने को इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थगित करती  
है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 35  
की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार  
द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा  
38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों  
के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि बैंक आौफ  
अंजावुर लिमिटेड को मंजूर की गयी अधिस्थान की काला-  
वधि के दौरान, वह बैंक भारतीय रिजर्व की लिखित  
अनुमति के बिना;

(क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्वहन में  
या अन्यथा कोई उधार या अतिरिक्त नहीं देगा,  
कोई दायित्व उपस्थित नहीं करेगा, कोई विनियोग  
नहीं करेगा, या किसी संवाद के लिए करार या  
उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके

पश्चात उपर्युक्त विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा :

- (1) प्रत्येक बचत या चालू खाते में या किसी अन्य निषेप में चाहे वह किसी भी नाम जात हो, कुल अतिशेष के 50 प्रतिशत में अनधिक राशि परन्तु यह तब तक कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की बाबत संदर्भ रकम की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रुपए तथा संस्थानों के मामले में 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी निषेपकर्ता मंस्था को जो किसी रूप में बैंक का छूटी है, संदर्भ नहीं की जाएगी ।
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्रॉफ्ट या संबंध आदेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसकी अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, असंबंध रह जाती है;
- (3) तारीख 19 अगस्त, 1989 को या उसमें पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात वसूल किए गए बिलों की रकम;
- (4) कोई ऐसा व्यय जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विस्तृत फाइल किए गए किसी बाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अधिप्राप्त डिक्री के संबंध में या उसको देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक बाद या अपील या डिक्री या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 रुपये से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अधिप्राप्त की जाएगी; और।
- (5) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहाँ तक वह बैंककारी कम्पनी के प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिये बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है, परन्तु जहाँ किसी मद पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छः केलेंडर मास के दौरान उस मद के मद्देह औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहाँ उक्त अवधि के दौरान उस मद के मद्देह कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे में मद पर व्यय 2,500 रुपये

से अधिक है वहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अधिप्राप्त की जाएगी ।

- (6) तारीख 19 अगस्त, 1989 को कारबाह की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुमति के सिवाए अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय अंतर या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा ।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि बैंक आफ थंजावूर लिमिटेड उसे मंजूर की गयी स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संदाय अर्थात् बैंक आफ थंजावूर लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुरूपी या किसी अन्य बैंक द्वारा बैंक आफ थंजावूर लिमिटेड को भरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विळुद्ध उधारों/अग्रियों के या दिए गए प्रतिदार के लिए आवश्यक है, और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंदर्भ है अतिरिक्त संदाय कर सकता है ।

4. केन्द्रीय सरकार, यह और निवेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान बैंक आफ थंजावूर लिमिटेड पूर्वोक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुशास्त होगी, परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं संगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तों का थंजावूर बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है ।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निवेश देती है कि बैंक आफ थंजावूर लिमिटेड अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किसी बिलों की, जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दिशा में धापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है ।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि बैंक आफ थंजावूर लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्नलिखित रीति में और विस्तार तक निर्मुक्त या परिदृष्ट कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या औबरझफट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है, आडमानित, विलंगमित या बंधक या अन्यथा प्रभारित किया गया है :—

- (1) किसी ऐसी दशा में जिसमें, यथास्थिति, उधार लेने वाले या उधार लेने वालों से वेय सभी रकमों के भवये पूर्व संदाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और

(2) किसी अन्य दशा में, अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो प्रधिस्थगन शादेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, नीत्र उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या सम्भव हो।

[सं. 17/5/89-बी ओ. III]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
(Banking Division)  
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th August, 1989

S.O. 652 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949) the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of Moratorium in respect of the Bank of THANJAVUR LTD. for the period from the close of business on the 19th August, 1989 upto and inclusive of the 19th December, 1989 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the Bank of THANJAVUR LTD. shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India, —

(a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :

(i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000 and in the case of institutions Rs. 25,000 and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way :

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
- (iii) the amounts of the bills received or collection on or before the 19th August 1989 and realised before, on or after that date;
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the Said Bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding in excess of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and
- (v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;
- (b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 19th August, 1989.
- 3. The Central Government hereby also directs that the Bank of THANJAVUR LTD. may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the Bank of THANJAVUR LTD., by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.
- 4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the Bank of THANJAVUR LTD., shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Bank of THANJAVUR LTD.

5. The Central Government hereby further directs that the Bank of THANJAVUR LTD., may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has a right to title or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the Bank of THANJAVUR LTD., may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or over draft —

- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally; and
- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17/5/89-BO-III]

का.आ. 653 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन, अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसधारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अल्लेवन प्रद विचार करने परस्कात् पाहर सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड की बाबत 19 अगस्त, 1989 को कारबाह की समाप्ति से तारीख 19 सितम्बर, 1989 तक जिसके अन्तर्गत, यह तारीख भी है, को कालावधि के लिए आधिस्थान आदेश करती है और अधिस्थगन की कालावधि के दोषम उस बैंककारी कम्पनी के बिल्ड सभी कार्यवाहयों और कार्यवाहयों के प्रारम्भ करने या बात रखने की इस शर्त के अधीन रहते हुए स्वयंत्र करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खण्ड (ब) के अधीन केन्द्रीय ग्रान्टर, द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उस अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं प्रहुङ्गा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निर्देश देती है कि पाहर सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड को मंजूर की गयी अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुशा के बिना—

(क) अपने दायित्वों और वास्तवियों के लिए हमें या अन्यथा कोई उधार या अधिम नहीं देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा, या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें उसके

पश्चात् उपर्युक्त विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझीता या छहराव नहीं करेगा।

- (1) प्रत्येक बधत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में बाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हों, कुल अतिशेष के 50 प्रतिशत से अनधिक राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी बन्ध व्यक्ति के साथ संयेकरण में नहीं) जमा खाते की बाबत संबंध रकम की कुल धनराशि अस्तियों के भाग्य में 10,000 रुपये तथा संस्थाओं के भाग्य में 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी निक्षेपकर्ता संस्था को जो किसी रूप में बैंक का अणी है, संदर्भ नहीं की जाएगी है, संदर्भ नहीं की जाएगी
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ब्राफट या संदाय अदेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसका अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, असंदर्भ रह जाती है;
- (3) जारी व. 19 अगस्त, 1989, को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस द्वारी या के पूर्व को या उसके पात्रात् वभूल किए गए बिलों की रकम;
- (4) कोई ऐसा व्यय उक्त बैंक द्वारा या उसके लिए किए गए किसी वाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अधिप्राप्त डिक्री के संबंध में या उसकी तथा किसी रकम को बमूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपयोग किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या डिक्री या कार्यवाही की बाबत व्यय 2,500 रुपये से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक को लिखित अनुशा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अधिप्राप्त की जाएगी; और
- (5) किसी अन्य पद पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी कम्पनी के प्रतिविन के ब्राफटन का संचालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है, परन्तु जहां किसी पद पर कुन वर अधिस्थान के आदेश के पूर्व उक्त बैंककारी कम्पनी के दौरान उस मद के मद्दे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ

है और ऐसे में मद पर व्यय 2500 रुपये से अधिक है वहाँ भारतीय रिजर्व बैंक को लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपयोग किए जाने के पूर्व अभिप्राप्ति की जाएगी।

(ब) तारीख 19 अगस्त, 1989 को कारबाह की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाय अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय अंतरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि पारुर सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड उसे मंजूर की गई स्थगन को कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संदाय, अर्थात् पारुर सेन्ट्रल लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुवंशीय किसी अन्य बैंक द्वारा पारुर सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड को सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों/अग्रिमों के या दिए गए प्रतिबाद के लिए आवश्यक है और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंदर्भ है अतिरिक्त संदाय कर सकता है।

4. केन्द्रीय सरकार, यह और निदेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान पारुर सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड पूर्वोक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक के पास अपना आता चलाने के लिए अनुशास्त हीनी, परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित भारतीय का पारुर सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि पारुर सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को, जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस विधा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि पारुर सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्नलिखित रीति में और विस्तार तक निमुक्त या परिवर्तन कर सकेगा जो किसी उधार मकद प्रत्यय या ओवरड्रॉफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है,

आचार्यानित, विलंगमित या बंधक या अन्यथा प्रभास्ति किया गया है :—

- (1) किसी ऐसा दशा में जिसमें, यास्तिव्यति, उधार लेने वाले या उधार लेने वालों से देय सभी रकमों के मुद्रे पूर्ण संदाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और
- (2) किसी अन्य दशा में, अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गये थे, इन दोनों में जो भी उच्चतर है, नोचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सोमाओं के अनुपात का कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या संभव हो।

[स. 17/7/89-बा ओ-III(i)]

S.O. 653(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the PARUR CENTRAL BANK LTD, for the period from the close of business on the 19th August, 1989 upto and inclusive of the 19th December, 1989 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the PARUR CENTRAL BANK LTD., shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—

(a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder.

(i) A sum not exceeding 5% per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000/- or in the case of institutions Rs. 25,000/- and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
  - (iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 19th August 1989 and realised before, on or after that date;
  - (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2500/- the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and
  - (v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;
- (b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 19th August, 1989.

3. The Central Government hereby also directs that the PARUR CENTRAL BANK LTD. may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the PARUR CENTRAL BANK LTD. by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the PARUR CENTRAL BANK LTD. shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the PARUR CENTRAL BANK LTD.

5. The Central Government hereby further directs that the PARUR CENTRAL BANK LTD. may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the PARUR CENTRAL BANK LTD., may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit overdraft —

- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally; and
- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17/89-80-III(i)]

#### अधिकृतना

का. आ. 654 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विभिन्नमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् पूर्वीवल बैंक लिमिटेड की बाबत 19 अगस्त, 1989 को कारबाह की समाप्ति से तारीख 19 दिसम्बर, 1989 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि के लिए अधिस्थगन आदेश करती है और अधिस्थगन की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विश्व सभी कार्यालयों और कार्यालयों के प्रारम्भ करने या चालू रखने को इस शर्त के अधीन रखते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थान में उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन मारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिष्ठृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निश्चा देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड को मंजूर की गयी अविस्थान का कालावधि के दौरान, वह बैंक मारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना —

(क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं से विच्छन में या अन्यथा कोई उधार या अप्रिम नहीं देगा,

कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा, या किसी संदाय के लिये करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझौता या छहराव नहीं करेगा:—

- (1) प्रत्येक बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निशेप में जाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, कुल अतिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की की बाबत संबंध रकम की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रुपये तथा संस्थाओं के मामले में 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी निशेपकर्ता संस्था को जो किसी रूप में बैंक का अहणो है, संबंध नहीं की जाएगी;
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संबंध की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, असंबंध रह जाती है;
- (3) तारीख 19 अगस्त, 1989 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिये प्राप्त और उस तारीख से पूर्व को या उसके पश्चात बसूल किए गए बिलों की रकम;
- (4) कोई ऐसा व्यक्ति जो बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए किसी बाद या अपील के संबंध में या उक्त बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिक्टी के संबंध में या उसको देय किसी रकम को बसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक बाद या अपील या डिक्टी या कार्यालयी की बाबत व्यय 2,500 रुपये से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अधिप्राप्त की जाएगी; और
- (5) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी के प्रतिशिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है, परन्तु जहां किसी मद

पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छः केलेंडर माह के दौरान उस मद के महे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां उक्त अवधि के दौरान उस मद के महे कोई अन्य उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे में मद पर व्यय 2,500 रुपये से अधिक है वहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी।

- (6) तारीख 19 अगस्त, 1989 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाए अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, अंतरण या उसका अन्यथा व्यय नहीं करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार सरकार यह भी निदेश देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड उसे मंजूर की गयी स्थगन की कालावधि के द्वारा निम्नलिखित और संबंध, अर्थात् पूर्वांचल बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुष्ठीय किसी अन्य बैंक द्वारा पूर्वांचल बैंक लिमिटेड को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों/अग्रिमों के या विए गए प्रतिदाय के लिये आवश्यक है और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंबंध है अतिरिक्त संबंध करसकता है।

4. केन्द्रीय सरकार, यह और निदेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान पूर्वांचल बैंक लिमिटेड पूर्वांचल संबंध करने के प्रयोजन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता, छलाने के लिये अनुज्ञा होगी परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लागता जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वांचल बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अविरोधित शर्तों का पूर्वांचल बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को जिनकी बसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दिशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निर्देश देती है कि पूर्व-बल वैदिक एसे माल या प्रतिभूतियों को निम्नालिखित रीति में और वितार तक निर्मुक्त या परिवर्तन कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रश्न या ओवरड्रॉफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है आडमानित, विलग मित या बंधक या अन्यथा प्रभावित किया गया है:—

- (1) किसी ऐसो दशा में जिसमें यथास्थिति, उधार लेने वाले या उधार लेने वालों में ऐसे वर्षों रकमों के महे पूर्ण संदाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और
- (2) किसी अन्य दशा में अनुष्ठित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो तीव्र उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या संभव हो।

[स. 17 /7/89 वी ओ. III (ii)]

S.O. 654(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949) the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the PURBANCHAL BANK LTD. for the period from the close of business on the 19th August, 1989 upto and inclusive of the 19th December, 1989 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the conditions that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the PURBANCHAL BANK LTD. shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—

- (a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :
- (i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the

name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000 and in the case of institutions Rs. 25,000 and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force :
- (iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 19th August, 1989 and realised before, on or after that date :
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and
- (v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;
- (b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 19th August, 1989.
3. The Central Government hereby also directs that the PURBANCHAL BANK LTD. may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the PURBANCHAL BANK LTD. by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.
4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the PURBANCHAL BANK LTD. shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with

any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the PURBANCHAL BANK LTD.

5. The Central Government hereby further directs that the PURBANCHAL BANK LTD. may during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the PURBANCHAL BANK LTD. may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft :

- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Bank, unconditionally; and
- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17/7/89-80-III(ii)]

का. आ. 655(अ).—केन्द्रीय सरकार बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1649 का 10) की धारा 46 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड की बाबत 19 अगस्त 1989 को कारबाह की समाप्ति से तारीख 19 दिसम्बर 1989 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है की कालावधि के लिये अधिस्थगन आदेश करती है और अधिस्थगन को कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्यवाईयों और कार्यवाईयों के प्रारम्भ करने या आलू रखने की इस शर्त के अधीन रहते हुए रथगत करती है कि ऐसे स्थवर से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निर्देश देती है कि बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड को मंजूर की गयी अधिस्थगन की कालावधि के दौरान वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना —

- (क) अपने दायित्वों और वाध्यताओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई उठार या अग्रिम नहीं

देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनियमन नहीं करेगा या किसी संदाय के लिए करार या उसका मंचितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त विस्तार और रोति के सिवाएँ कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा :—

- (1) प्रत्येक बैंक या चालू खाते में या विनी अन्य निशेष में नाहे वह किसी भी नाम में जात हो, कुल अतिशेष के 50 प्रतिशत से अनधिक राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ मंयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की बैंक संदत्त रकम की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रुपये तथा मंस्थाओं के मामले में 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी निशेषकर्ता मंस्था को जो किसी रूप में बैंक का अणी है, संदत्त नहीं की जाएगी।
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संदाय आदेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिस को अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, असंदत्त रह जाती है ;
- (3) तारीख 19 अगस्त, 1989 को या उससे पूर्व सम्प्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात् वसूल किए गए विलों की रकम ;
- (4) कोई ऐसा व्यय जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विस्तर काईल किए गए किसी वाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिक्टी के संबंध में या उसको देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील डिक्टी या कार्यवाही वी बाबत व्यय 2500 रु. से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अधिप्राप्त की जाएगी; और
- (5) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक बैंककारी कम्पनी के प्रति दिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए, बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है, परन्तु जहां किसी मद पर कूल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व 75 कैलेंडर मास के दौरान उस मद के मदे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां उक्त अवधि के दौरान उस मद के मदे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे में मद पर व्यय 2500 रुपये से

अधिक है वहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अनिवार्य व्यवहार उपरान्त किए जाने के पूर्व अभिप्राप्ति की जाएगी।

(ब.) तारीख 19 अगस्त, 1989 को कारबाह की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए कारबाह के अनुसरण के सिवाएँ अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय अंतरण या उसका अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी निर्देश देती है कि बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड उसे मंजूर की गयी स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संदाय, अर्थात्:- बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुपाती या किसी अन्य बैंक द्वारा बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारण/अप्रिमों के या दिए गए प्रतिदाय के लिए आवश्यक है, और जो उस तारीख को जिसकी अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंघत है, अनिवार्य संदाय कर सकता है।

4. केन्द्रीय सरकार, यह और निर्देश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड पूर्वीकृत संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुशासन होगी, परन्तु इस आदेश को किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वीकृत बैंक में अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित जर्तीं का बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड के पथ में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निर्देश देती है कि बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड अधिस्थीत की कालावधि के दौरान ऐसे किन्हीं विलों को जिनकी वस्तु नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उम दिशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे विलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निर्देश देती है कि बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्नलिखित रोति में और विस्तार तक नर्मुक्त या परिदृष्ट कर सकेगा जो किसी उधार नकद प्रत्यय या ओवर च्रूफट के लिए इसके पास गिर्वाई रखा गया है, आइमानित विलंगमित या वंश्रक या अन्यथा प्रभारित किया गया है:—

(1) किसी ऐसी दशा में जिसमें यथास्थिति, उधार लेने वाले या उधार देने वालों से देय सभी रकमों के मध्ये पूर्ण संदाय बैंक द्वारा

बिना जर्ती के प्राप्त कर लिया गया है; और

(2) किसी अन्य दशा में, अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए ये इन दोनों में के जो भी उच्चसर हों, तो उन्हें उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सौमोद्दों के अनुपात की कम किए किए बिना ऐसी माला तक जो आवश्यक या संभव हो

[सं. 17/7/89-बी आ III (iii)]

मन्त्रेवर जा, संयुक्त सचिव

S.O. 655 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949) the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under Sub-Section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the Bank of TAMILNAD LTD., for the period from the close of business on the 19th August, 1989 upto and inclusive of the 19th December, 1989 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the Bank of TAMILNAD LTD., shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—

(a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :

(i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000/- and in the case of institutions Rs. 25,000/- and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;

(ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining

- unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
- (iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 19th August, 1989 and realised before, on or after that date;
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceedings is in excess of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and
- (v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that is on during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;
- (b) Sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 19th August, 1989.
3. The Central Government hereby also directs that the Bank of TAMILNAD LTD. may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities, to the Bank of TAMILNAD LTD. by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.
4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the Bank of TAMILNAD LTD., shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Bank of TAMILNAD LTD.
5. The Central Government hereby further directs the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.
6. The Central Government hereby also directs that the Bank of TAMILNAD LTD., may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft —
- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally; and
  - (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17/7/89-BO-III(iii)]  
MANTRESHWAR JHA, Lt. Secy.

